GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 259
TO BE ANSWERED ON 28TH MARCH, 2022

FDI IN DEFENCE SECTOR

*259 SHRI K.C. VENUGOPAL:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether Government has enhanced FDI in defence sector upto 74 per cent;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps Government is taking so that the purpose of self reliance should not be defeated and to strengthen R&D base of the country?

A N S W E R

MINISTER OF DEFENCE (SHRI RAJNATH SINGH)

(a) to (c) : A Statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 259 FOR ANSWER ON 28.03.2022 REGARDING 'FDI IN DEFENCE SECTOR'.

(a) to (c): Yes, Sir. Defence sector is driven by high-end technologies and innovations. The sector needs continuous investment for capacity enhancements and creation of state-of-the-art technologies and manufacturing facilities to address the requirements of Defence equipment / products. In pursuance of the "Make in India" policy, the indigenization of defence products and promotion of exports is being provided topmost priority. Large scale efforts are being made by the domestic industry to develop such capabilities, however, in areas where such capabilities do not exist, FDI by the Global OEMs help to bridge the gap. Besides, FDI also results in creation of economic opportunities while saving and bringing precious foreign exchange. Further, this gives push to India's policy of "Make in India & Make for the World".

Therefore, to give more thrust and promote FDI in defence sector, Government of India liberalized the FDI policy on 17.09.2020 allowing 74% FDI under automatic route and beyond 74% upto 100% through Government route wherever it is likely to result in access to modern technology. While doing so, sufficient safeguards are laid to ensure that security and strategic interests of our country are not compromised. During the period from 2001 – 2014, a total FDI inflow of about Rs 1382 crore was reported and from 2014 till date, a total FDI of about Rs 3343 crore has been reported.

In addition, the Government has taken many initiatives to strengthen self reliance, import substitution and promote R&D in Defence sector, which, inter-alia, include according priority to procurement of capital items from domestic sources under Defence Acquisition Procedure (DAP)-2020; Announcement of 18 major defence platforms for industry led design & development; Notification of two 'Positive Indigenisation Lists' of total 209 items of Services and one 'Positive Indigenisation List' of total 2851 items of Defence Public Sector Undertakings(DPSUs), for which there would be an embargo on the import beyond the timelines indicated against them; Simplification of Industrial licensing process with longer validity period; Simplification of Make Procedure; Launch of Innovations for Defence Excellence (iDEX) scheme involving startups & Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); Implementation of Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017; Launch of an indigenization portal namely SRIJAN to facilitate indigenisation by Indian Industry including MSMEs; Reforms in Offset policy with thrust on attracting investment and Transfer of Technology for Defence manufacturing by assigning higher multipliers; and Establishment of two Defence Industrial Corridors, one each in Uttar Pradesh and Tamil Nadu. Further, to strengthen the R&D base in defence sector, announcement has been made in the Union Budget 2022 – 23 earmarking 25% of the R&D Budget for industry led R&D.

*****

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 259

28 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***259. श्री के.सी. वेणुगोपाल :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आत्म-निर्भरता का प्रयोजन भी विफल न हो और देश का अनुसंधान और विकास का आधार भी मजबूत बना रहे, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

'रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 28 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 259 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): जी, हां । रक्षा क्षेत्र उच्च स्तर की प्रौद्योगिकियों और नवोन्मेषों से संचालित होता है । इस क्षेत्र को रक्षा उपस्करों / उत्पादों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि हेतु निरन्तर निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तथा विनिर्माण सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता है । "मेक इन इंडिया " नीति के अनुपालन में रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण और निर्यात संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । घरेलू उद्योग द्वारा ऐसी क्षमताएं विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि उन क्षेत्रों में जहां ऐसी क्षमताओं का अभाव है, वैश्विक ओईएम द्वारा एफडीआई से अंतर कम करने मे सहायता मिलती है । इसके अलावा, एफडीआई के परिणामस्वरूप बचत करने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के अलावा आर्थिक अवसर भी सृजित होते हैं । इसके अलावा, यह भारत की "मेक इन इंडिया और मेक फार दी वर्ल्ड" नीति को गति प्रदान करती है ।

इसलिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई पर और जोर देने तथा उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 17.09.2020 को एफडीआई नीति को उदारीकृत बनाया जिसमें आटोमैटिक रूट के जरिए 74 प्रतिशत तक एफडीआई और सरकारी रूट के जरिए 74 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति वहां पर दी गई है जहां पर आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए पहुंच बनने की संभावना होती है । ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित रक्षोपाय निर्धारित किए जाते हैं कि हमारे देश के सुरक्षा और सामरिक हितों के साथ कोई समझौता नहीं हो । वर्ष 2001-2014 की अवधि के दौरान लगभग 1382 करोड़ रु. की एफडीआई प्राप्ति की रिपोर्ट मिली थी और वर्ष 2014 से आज की तारीख तक लगभग 3343 करोड़ रु. की कुल एफडीआई प्राप्त होने की रिपोर्ट मिली है ।

इसके अलावा, सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आयात विकल्प को सुदृढ़ बनाने तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलें प्रारंभ की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के अन्तर्गत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत

मदों की खरीद को प्राथमिकता देना; उद्योग द्वारा अभिकल्पन और विकास के लिए 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों की घोषणा; सेनाओं की कुल 209 मदों की दो 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 2851 मदों की एक 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' की अधिसूचना; जिनके लिए उनके समक्ष दर्शाई गई समय सीमा के बाद से आयात पर व्यापार प्रतिषेध होगा; लम्बी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण ; स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार (आईडेक्स) योजना का शुभारंभ ; सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को वरीयता) आर्डर 2017 का कार्यान्वयन ; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को सुकर बनाने के लिए सृजन नामक स्वदेशीकरण पोर्टल का शुभारंभ; उच्च गुणकों द्वारा रक्षा विनिर्माण के लिए निवेश को आकर्षित करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल देने के साथ ऑफसेट नीति में सुधार करना और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु , प्रत्येक में एक-एक, रक्षा औद्योगिक कारिडोर की स्थापना करना सम्मिलित हैं । इसके अलावा, केन्द्रीय बजट 2022-23 में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास आधार को सुदृढ़ करने के लिए उद्योग द्वारा संचालित आर एंड डी के लिए आर एंड डी बजट का 25 प्रतिशत निर्धारित करने की घोषणा की गई है ।

****

SHRI K. C. VENUGOPAL: There are tall claims made about the policy of "Make in India and Make for the World", especially in Defence sector. The Government of India has liberalised the FDI policy by giving 76 per cent of the Foreign Direct Investment in the Defence sector. My question is, has this change of policy strengthened our indigenous production on Defence sector, especially the public sector unit of Defence sector? Now we are hearing that Government of India's intention is to privatise the public sector of the Defence sector itself and that we are very rich in the MSME sector in India. Is the Government taking any initiative to increase the indigenous production in Defence Sector by strengthening public sector and MSME sector?

श्री अजय भट्ट : मान्यवर, यह बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं कोशिश करूँगा कि इसके माध्यम से सदन को काफी जानकारी उपलब्ध कराऊँ। हमारी भारत सरकार ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सुरक्षा तब ही मजबूत होगी, जब हम टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2001 में जो एनडीए गवर्नमेंट थी, उसने पहली बार डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ जहाँ हमें 2001 से 2014 तक, 14 सालों में केवल 215 लाइसेंस मिले, वहीं हमने मात्र सात सालों में, यह जो हमारी दूसरी अवधि है, जब से माननीय प्रधान मंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, अभी तक 353 लाइसेंस इश्यू किए हैं। इसके साथ ही, यह भी बताना उचित होगा कि 2001 से 2014 तक, यानी 14 वर्षों में जहाँ हमें डिफेंस और aerospace inflow में 1,382 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, वहीं इन सात सालों में हमारी सरकार ने 3,343 करोड़ एफडीआई achieve किया है, जो एक बहुत बड़ी राशि है। इसके साथ ही, डिफेंस सेक्टर high-end technologies and innovations द्वारा संचालित है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI K. C. VENUGOPAL: No, no; what action has been taken? ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... आप briefly बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अजय भट्ट : मैं आपको पूरी जानकारी और आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी में दे रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All of you please sit down. Let him reply. ...*(Interruptions)*...

श्री अजय भट्ट : मेरा उत्तर आने दीजिए, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ...(**व्यवधान**)... इसमें काफी जानकारी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप चेयर को एड्रेस करिए और संक्षेप में रिप्लाई दीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री अजय भट्ट : ठीक है, मान्यवर।

मान्यवर, एनडीए गवर्नमेंट ने 2001 में जो डिफेंस सेक्टर खोला था, उससे हमें काफी लाभ हो रहा है। जो आपने पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए सब चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन जब कहीं कोई ऐसी चीज़ें बनाने की जरूरत होती है, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होती हैं, वहाँ हम एफडीआई को लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारा रोजगार बढ़ता है, सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं। **...(व्यवधान)...** मान्यवर, हमने डिफेंस सेक्टर में जो प्रोडक्शन किया है, हमने इसमें पब्लिक सेक्टर को भी सौंपा है। पब्लिक सेक्टर भी इसमें आएगा, गवर्नमेंट के सेक्टर भी इसमें आएंगे, साथ ही, हमारी जितनी भी डीपीएसयूज़ थीं, उनके संबंध में आपको पता है कि हमने Ordnance को अलग करके सात डीपीएसयूज़ बना दी हैं और डीपीएसयूज़ भी ऐसी बनाई हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी competition करेगा और हमारी डीपीएसयूज़ भी competition करेंगी। मान्यवर, इससे देश को लाभ ही लाभ हो रहा है, कहीं पर कोई हानि नहीं है।

SHRI K. C. VENUGOPAL: My first specific question, how the Government has succeeded in increasing the indigenous production to public sector and MSME sector, has not been replied to. My second supplementary is very clear. Is the Government taking any coordinated efforts between private and public sector undertakings of Defence sector? My question is, after liberalising the FDI to 76 per cent, there is not much attraction from Foreign Direct Investment that is coming. Why is it so? Has the Government studied this factor? Now the Minister is saying, from 2014 to 2022, a total FDI of about Rs. 3000 crores has been reported. Is it a fact? My question is very clear.

श्री उपसभापति : माननीय के.सी. वेणुगोपाल जी, आपने पूरे दो क्वेश्चंस पूछ लिए। माननीय मंत्री जी।

श्री अजय भट्ट : सर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने भारतीय उद्योग जगत को विश्वास दिलाने के लिए हमारा जो वर्ष 2022-23 का यूनियन बजट है, उसमें कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए बजट का 68 प्रतिशत डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए निर्धारित किया है, जो कि कम नहीं होता है। इसको निर्धारित करने का यह बहुत बड़ा पार्ट है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमने आत्मनिर्भरता के लिए जो लिस्ट बनाई है, नोटिफिकेशन किया है, उसमें हमने 209 डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और हथियार शामिल किए हुए हैं। DPSUs के 2,851 आइटम्स का positive indigenisation realistic का नोटिफिकेशन भी हमने किया हुआ है। मान्यवर, इसमें किसी प्रकार की शंका का कोई कारण ही नहीं है। हमने यह एक बहुत अच्छा विषय लिया

हुआ है। इसमें हम जो एफडीआई को ला रहे हैं, वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ला रहे हैं। 74 प्रतिशत तो हम डायरेक्ट ला रहे हैं और इसे 100 प्रतिशत करने के लिए, हम बाकी गवर्नमेंट के through ला रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : सुश्री दोला सेन जी। **...(व्यवधान)...**प्लीज़, **...(व्यवधान)...** दोला सेन जी, आप क्वेश्चन पूछिए।

सुश्री दोला सेन : सर, डिफेंस के corporatization का जो पॉलिसी डिसीज़न है, हम उसके भी खिलाफ हैं और पश्चिमी बंगाल के कोलकाता से ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड का हेड ऑफिस हटा दिया, उसके भी खिलाफ हैं।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए।

सुश्री दोला सेन : लेकिन, यह पॉलिसी डिसीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। मेरा क्वेश्चन यह है कि why is the Ministry not declaring the Ministerial Cadre permanent employees of the OFB as surplus, so that they can get suitable placement in any other Central Government concern according to their option? And, why is the Ministry not up to the mark to protect the contractual workers to be secured for their job and may get salary without wage cut through GeM tender process done by the Central Government?

श्री अजय भट्ट : सर, माननीय सदस्या ने जो पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम कहीं से कहीं तक कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ से कोई कटौती नहीं हो रही है। जितने आवश्यक employees चाहिए, जितने भी रोज़गार के लिए सक्षम specialists चाहिए, वे सब के सब हमारे पास उपलब्ध हैं। **...(व्यवधान)...** मान्यवर, हमारा जो Ordnance sector था, वह पहले बिखरा पड़ा था। उसमें कोई यहाँ था, कोई वहाँ था, वे सब अलग-अलग थे और उनका मैनेजमेंट भी अलग-अलग लोग देख रहे थे। हमने सिर्फ यह किया कि इस बार उसको अच्छी तरह से organize कर दिया और हरेक के लिए अलग-अलग चीज़ें बना दीं। जैसे, अगर बुलेटप्रूफ जैकेट बनानी है, तो एक यहाँ बना रहा था, एक वहाँ बना रहा था और उनके मैनेजमेंट भी अलग-अलग थे, तो उसको हमने एक सेक्टर बना दिया। अगर कोई गन बना रहा था, तो वे भी बिखरे पड़े थे, उसको भी हमने एक सेक्टर बना दिया। इसी तरह, जो रॉकेट बना रहे थे, उनको भी हमने एक सेक्टर बना दिया और अब वे बिखरे नहीं हैं। आज हमारा प्रबंधन एक है और एक को ही उसकी पूरी जिम्मेदारी हमने दे दी है। इसलिए आप अपने मन से यह शंका बिल्कुल निकाल दें कि हम लोग किसी को कहीं से निकाल रहे हैं या बेरोज़गार कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : दोला जी, प्लीज़ आप बैठकर न बोलें। माननीय प्रेम चंद गुप्ता जी।

श्री प्रेम चंद गुप्ता : सर, सरकार ने अपने जवाब में self-reliance के बारे में कहा है, तो हमारी शुरू से ही self-reliance की पॉलिसी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मान्यवर, यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद जिस प्रकार से technological change in warfare and even in conventional warfare and weaponry system में आया है, उसको न प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, न पब्लिक सेक्टर कर सकता है और न ही उसको MSME कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार Government-to-Government basis पर इस टेक्नोलॉजी को किसी तरह से obtain करे, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके।

श्री अजय भट्ट : यह सुझाव है। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रेम चंद गुप्ता : नहीं, यह सुझाव नहीं है। मेरा प्रश्न है कि उसके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री अजय भट्ट : ठीक है, सर। यह इनका सजेशन है।

श्री उपसभापति : ठीक है। माननीय बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य जी।

श्री प्रेम चंद गुप्ता : सर, यह मेरा सजेशन नहीं है। मेरा प्रश्न है कि इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? यह मेरा सुझाव नहीं है। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : माननीय प्रेम चंद जी, आपने पहले सुझाव ही दिया था।

श्री प्रेम चंद गुप्ता : लेकिन, I corrected myself, Sir.

श्री अजय भट्ट : महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से सक्षम है, देश चारों तरफ से चाक-चौबंद है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हर समस्या का समाधान करने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, the hon. Finance Minister, in her Budget Speech, has given priority to domestic production in Defence sector. Accordingly, she has, in the Budget, earmarked more than 60 per cent for domestic production. I would like to know from the hon. Minister about the roadmap prepared by the Government to utilize this Budget allocation. In our country, two Defence Corridors are already working -- one is in Uttar Pradesh and another one in Tamil Nadu. I would like to know whether the Government is considering to go for more domestic

production Defence Corridors in other parts of the country, including in the North-Eastern parts of the country.

श्री अजय भट्ट : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो कॉरिडोर बने हुए हैं। देश के बाकी हिस्सों में भी जब, जहां, जैसी ज़रूरत होती है, उसके लिए सरकार समय-समय पर निर्णय लेती रहती है।

मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो इन सात सालों में पहली बार हम कम से कम 72 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। SIPRI नामक संस्था, जो international authority है, उसने बताया है कि पहली बार हम 25 टॉप देशों में आगे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए किसी भी शंका को मैं बहुत सार्थक नहीं मानता हूं। इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद है, हम सुरक्षित हैं और हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं और हमारी सेना का मनोबल काफी ऊंचा उठा है।

श्री राजनाथ सिंह : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य के.सी .वेणुगोपाल जी ने DPSUs के संबंध में जानना चाहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी steps लिए जा रहे हैं, उनके कारण कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि DPSUs का प्रोडक्शन गिर रहा हो अथवा वे लॉस में जा रही हों, कुछ इस प्रकार की चिंता कमोनेश उन्होंने व्यक्त की थी। उस संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक DPSUs का प्रश्न है, सरकार द्वारा उनको पूरी तरह से equity support देकर मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको strengthen किया जा रहा है।

दूसरा यह कि उनकी अब तक की जो committed liabilities रही हैं, उनको भी हम clear कर रहे हैं, ताकि हमारी DPSUs किसी भी सूरत में कमज़ोर न पड़ें। साथ ही, जितना भी हो सकता है, हम DPSUs को maximum हाई लेवल ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आज भी हमारी DPSUs को 80 परसेंट ऑर्डर मिल रहा है, इसलिए DPSUs को weaken करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 260, माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी।